

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी- राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 02/2017

बउनवान

कालूलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री देवचन्द जाति-गुर्जर निवासी-खेडलीकेशो  
तहसील-बारां जिला-बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :-1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक - 04.02.2021**

1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 23.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-खेडलीकेशो, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, 500/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2- अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कानून अनुसार विवेचना न करके भारी भूल की है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को एक प्रकरण की कोई सूचना नहीं दी गई। गिरफ्तारी करने पर निर्णय की जानकारी हुई है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

3- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किये गये। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से पूर्व से कब्जा



छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये पश्चात्वर्ती मानकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1016/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1016/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 370/2016 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( राजेन्द्र विजय )  
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)